

सामाजिक उत्तरदायित्व : इंडिया इंक के खर्च में शिक्षा-स्वास्थ्य की अधिक हिस्सेदारी

सीएसआर खर्च तीन गुना बढ़ा, हिन्दुस्तान जिंक ने राज्य में किया ₹1750 करोड़ खर्च

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. भारतीय कंपनियों का कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) खर्च एक दशक में तीन गुना बढ़ा है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, सीएसआर पर खर्च वर्ष 2014-15 में 10,066 करोड़ रुपए था, जो 2023-24 में बढ़कर 34,909 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसमें सबसे अधिक खर्च शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर हुआ। कुल सीएसआर खर्च में शिक्षा क्षेत्र की हिस्सेदारी 34.8% तो स्वास्थ्य क्षेत्र की 20.5% रही।

देश की सबसे बड़ी जिंक उत्पादक कंपनी हिन्दुस्तान जिंक राजस्थान में वर्ष में 2016 से अब तक सीएसआर में 1,750 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करके सामाजिक प्रभाव के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। कंपनी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका, जल और स्वच्छता, महिला सशक्तीकरण और खेल सहित विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से राजस्थान के सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में उभरी है। कंपनी की दावा है कि इसके प्रयासों से प्रदेश के 23,000 से अधिक गावों में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के साथ, अलग-अलग परियोजनाओं से अब तक 23



गुप पर बहुत ज्यादा कर्ज : वाइसरॉय

अमरीका की शॉर्ट-सेलर कंपनी वाइसरॉय रिसर्च ने वेदांता गुप की वित्तीय स्थिति पर एक गंभीर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया कि वेदांता समूह की वित्तीय हालत ठीक नहीं है। गुप पर बहुत ज्यादा कर्ज है और यह ठीक से काम नहीं कर रहा है। इससे लेनदारों को भारी नुकसान हो सकता है। शॉर्ट सेलर ने वेदांता रिसोर्सिज लिमिटेड को एक पॉजी स्कीम बताया है। इससे वेदांता के शेयर 3.29% और हिन्दुस्तान जिंक के शेयर 2.50% टूट गए।

लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। कंपनी ने 2,500 आंगनवाड़ियों को नंद घर का रूप दिया, महिलाओं के लिए पोषण, डिजिटल शिक्षा,

वाइसरॉय रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा : वेदांता

वेदांता गुप ने खुद पर लगे आरोपों का खंडन किया है और वाइसरॉय रिसर्च की रिपोर्ट को बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण करार देते हुए सिरों से खारिज कर दिया। कंपनी ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि यह रिपोर्ट बिना किसी संवाद या पुष्टि के प्रकाशित की गई है। इसका मकसद झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना है। गुप ने कहा कि यह रिपोर्ट बदनाम करने के लिए जारी की गई है। रिपोर्ट को सनसनीखेज बनाकर लाभ कमाने की कोशिश की गई है।

स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास प्रदान करती है। इन केंद्रों से वित्त वर्ष 2025 में 3.5 लाख से अधिक बच्चों और माताओं को लाभ हुआ है।